Fax : 0512-2332222 (S.O.)
011-23212648 (C.O.)

Ph.: 0512-2332222
Mob.: 09415726924

सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ

Govt. Employees National Confederation

(AFFILIATED TO B.M.S.)

CENTRAL OFFICE : RAM NARESH BHAVAN, TILAK GALI, PAHAR GANJ, NEW DELHI - 110055

प्रस्ताव

सरकारी संस्थानो का निगमीकरण/निजीकरण का विरोध

देश की आजादी के बाद देश के औद्योगिक ढाँचे को खड़ा करने वाले एवं एक बड़ी संख्या मे रोजगार पैदा करने वाले देश के सरकारी संस्थानो जैसे रेलवे, आयुध निर्माणियाँ, सेना कार्यशालाएँ, डाक सेवाएँ आदि को निगमीकरण/ निजीकरण किये जाने पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। बहुत हद तक सरकार इस दिशा मे काफी आगे बढ़ चुकी है।

पूंजीवादी सोच से प्रभावित सरकार मे बैठे अधिकारियो एवं जनप्रतिनिधियो द्वारा सरकारी संस्थानो की उपेक्षा प्रारम्भ कर दी गयी है। वे आम नागरिको मे ये धारणा पैदा कर रहे है कि देश निर्माण मे मात्र निजी क्षेत्र का ही योगदान रहा है, सरकारी क्षेत्र देश के नागरिको पर बोझ है।

ऐसी धारणा का प्रचार करते समय वे सन् 1962 भारत–चाइना युद्ध, 1965 भारत– पाकिस्तान युद्ध, 1971 भारत– पाकिस्तान युद्ध, 1999 कारगिल युद्ध मे आयुध निर्माणियो के योगदान को भूल जाते है। वे भूल जाते है कि आज भी रेलवे भारतीय अर्थव्यवस्था की धड़कन है। डाक सुदुर भारत मे रह रहे भारत के नागरिको हेतु संचार व सम्पर्क की धुरी है।

भारतीय रेल के 109 लाभ के मार्गो पर 151 यात्री गाड़ियो को निजी क्षेत्र के द्वारा चलाने के लिए रेलमंत्रालय ने निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया है, विश्व के उन देशो पर यदि नजर डाली जाय तो जिन–2 देशो मे रेल संचालन निजी क्षेत्र के हाथो मे दिया गया है, वहाँ सफल न होने के कारण रेलवे को पुनः सरकारी क्षेत्र मे लाने की योजना बनायी जा रही है। इतना ही नही निजी/ निगम/ कॉपरेटिव क्षेत्रो की लाखो–लाख इकाईयाँ बन्द हो गयी है अथवा बन्दी के कगार पर है और लाखो–लाख मजदूर बेरोजगारी का सामना कर रहे है। यह सत्य है कि निजी संस्थान रेल का संचालन मुनाफा कमाने के लिए करेगा, न कि सेवा की भावना से। भारत जैसे गरीब देश जहाँ के लगभग 80 करोड़ जनता को जीवित रहने के लिए सरकारी मुफ्त राशन पर निर्भर रहना पड़ता है, उस गरीब देश मे मंहगी रेल यात्रा क्या जनता के हित मे होगी ?

सरकारी क्षेत्र के भारतीय रेल मुनाफे के चिंता किये बिना सम्पूर्ण देश के शहरी क्षेत्र से लेकर दुर्गम दूरस्थ क्षेत्रो को देश की मुख्य धारा से जोड़ती है। निजी संस्थानो द्वारा चलाये जाने वाले रेल का एकमात्र उद्देश्य होगा अधिक मुनाफा कमाना। इसलिए दूरस्थ क्षेत्रो की बजाय वे अधिक राजस्व उत्पादक रेल पथो पर अधिक ट्रेन चलायेंगे। मेट्रो शहरो का विकास होगा। दूरस्थ क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से अलग थलग होंगे। जिसके कारण देश के ग्रामीण शहरी क्षेत्र के विकास मे विषमता पैदा होगी।

भारतीय रेल का लाभ यह है कि यह मुनाफा का विचार किये बिना अपने सामाजिक दायित्व पूरा करने मे अहम भूमिका अदा करती है। करोना महामारी के दौरान भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए इसने देश के कोने कोने मे निर्बाध आपूर्ति श्रृंख्ला को बनाये रखा। रोगी एवं करोना योद्धाओ की जीवन रक्षा के लिए बड़ी संख्या मे रेल कोचो को आइसोलेशन वार्ड मे परिवर्तन, पी0पी0ई0 किट, वेण्टीलेटर बेड आदि का आपात स्थिति मे निर्माण किया, रेल कर्मचारियो के इस योगदान को स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी अपने सम्बोधन मे स्वीकार करते हुए भारतीय रेल को देश की सुरक्षा की दूसरी पंक्ति का डिफेन्स फोर्स बताया। यदि रेल निजी क्षेत्र के स्वामित्व मे होता तो यह संभव नही होता।

भारतीय रेल देश के सबसे बड़े नियोक्ताओ मे से एक है। निजीकरण से स्थायी/ मर्यादित रोजगार को भारी नुकसान होगा। बेरोजगारी से जूझ रहे देश मे और बेरोजगारी की समस्या मे वृद्धि होगी। समाज अशान्ति का शिकार होगा।

हम निजीकरण व निगमीकरण मे डाले गये संस्थानो की दुर्दशा भी देख चुके है। चाहे भारत संचार निगम लि0 हो या महानगर संचार निगम लि0। एयर इण्डिया को निजी क्षेत्र को बेचने के निर्णय ने सरकार की अक्षमताओ को पूरी तरह उजागर कर दिया है।

ऐसा सरकार का मानना हो सकता है कि सरकार को उद्योग धन्धो से दूर रहना चाहिए जबकि भारतीय समाज व वर्तमान अर्थव्यवस्था मे सरकारी क्षेत्र के रोजगार समाज के निम्न वर्ग के नागरिको को एक अच्छी जिन्दगी गुजारने हेतु एक बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते है। यदि सरकारी क्षेत्र समाप्त कर दिया जाता है तो ये नागरिक पूंजीपतियो के शोषण का साधन मात्र रह जायेंगे।

हाल मे ही, केन्द्र सरकार द्वारा रेलवे की उत्पादनशालाओ को निगमीकरण करने का निर्णय लिया गया है। यह रेलवे के कारखाने सफलतापूर्वक कार्य करते हुए रेलवे के लिए इंजन, रेलकोच आदि का सफलतापूर्वक निर्माण कर रहे है। कर्मचारियो के मन मे ये प्रश्न है कि जब कोई कारखाना घाटे मे नही है फिर इनका निगमीकरण क्यो किया जा रहा है? इस निर्णय से इन रेल कारखानो मे काम करने वाले कर्मचारियो मे अपनी नौकरी जाने का भय व्याप्त हो रहा है।

इसी प्रकार रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग (डी0डी0पी0) के अन्तर्गत कार्य कर रही 41 आयुध निर्माणियाँ अपनी सशस्त्र सेनाओ के लिए विभिन्न रक्षा उपकरण गोला बारूद, तोप, टैंक, विभिन्न प्रकार के रायफल और छोटे अस्त्र तथा विभिन्न प्रकार के कॉमबैट यूनीफार्म, पैराशूट और विभिन्न प्रकार की सामग्री का उत्पादन कर रही है। इन कारखानो की स्थापना वार रिजर्व के रूप मे की गयी थी और ये सेनाओ की आवश्यकताओ की आपूर्ति हेतु लंबे समय से कार्यरत है।

इन 41 आयुध निर्माणियो को वर्कलोड की समस्या से हमेशा जूझना पड़ता है। वर्कलोड कभी बहुत अधिक तो कभी बहुत ही न्यूनतम कर दिया जाता है। एक वर्ष के अन्दर ही रक्षा उत्पाद कई बदलते रहते है जिसके कारण यह कारखाने कभी भी लाभ अर्जित नही कर सकते है। वर्कलोड की अनिश्चितता के कारण इनके स्वरूप को बदलना इन कारखानो को बंद करने जैसा साबित होगा। जब बहुत अधिक काम होगा तो कर्मचारी अपने वेतन भत्ते कमा सकते है और जब बहुत कम काम होगा तो अपने वेतन भत्ते कैसे कमाएगें ?

ऐसा भी देखने मे आया है कि वर्कलोड देने के बाद समय पर इंडेण्ट नही दिए जाते जिससे आवश्यक कच्चे माल की खरीददारी नही हो पाती। कई बार अचानक बजट मे कटौती कर दी जाती है। यदि निगमीकरण किया जाता है तो यह कारखाने कुछ ही दिनो मे घाटे मे आकर बंदी की कगार पर पहुँच जाएगें। आपातकालीन स्थितियो मे या युद्ध के समय यह कारखाने अपनी सेनाओ को युद्ध सामग्री उपलब्ध कराने के लिए रात दिन एक करते है इनके बंद होने से देश की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न होगा।

रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत देश भर मे ई0एम0ई0 स्टेशन वर्कशॉप को बंद करने का निर्णय लिया गया तथा इनके स्थान पर एस0आर0आई0 की स्थापना की जा रही है जिनमे आर्मी के रिटायर्ड और आर्मी पर्सनल से कार्य कराया जा रहा है। वर्षो से मेंटीनेन्स कार्य करते आ रहे सिविलियन कर्मचारियो को हटाया जा रहा है। जिससे इन वर्कशॉप मे कार्यरत कर्मचारियो का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। इन कर्मचारियो का दूसरे संस्थानो मे भी समायोजन नही हो पा रहा है। साथ ही आर्मी बेस वर्कशॉप जिनकी संख्या स्वतन्त्र भारत मे आठ है। इन्हे गोको मॉडल मे चलाये जाने पर विचार किया जा रहा है। जिससे यहाँ पर कार्यरत सिविलियन कर्मचारियो का भविष्य भी अंधकारमय हो रहा है।

डी0जी0ओ0एस0 के अंतर्गत कार्य कर रहे चार डिपो सी0ओ0डी0 छिवकी इलाहाबाद, सी0ओ0डी0 शकूरबस्ती, सी0वी0डी0 दिल्ली एवं वी0डी0 पानागढ़ को बंद करने का निर्णय भी लिया गया है जिससे इन डिपो मे काम करने वाले कर्मचारियो का भविष्य अंधकारमय हो रहा है।

ऐसा भी जानकारी मे आया है कि पोस्टल विभाग मे पी0एल0आई0 (पोस्टल लाइफ इन्श्योरेन्स) का भी निगमीकरण किया जा रहा है।

ये भी एक विडम्बना है कि जो सरकारे देश चलाने का बड़ा बड़ा दावा करती हैं, वे इन छोटे छोटे संस्थाने को चलाने मे पूरी तरह अक्षम दिखाई देती है जिसकी मुख्य वजह यह है कि वे पूंजीपतियो को लाभ पहुँचाने के चक्कर मे इन संस्थानो को चलाने के लिए अनिच्छुक है।

सरकारी संस्थानो के प्रति उदासीनता एवं निजी संस्थानो को प्रोत्साहन से इनमे कार्य कर रहे कर्मचारियो मे डर एवं रोष की भावना व्याप्त हो रही है।

अतः भारतीय मजदूर संघ के इस 19वें अधिवेशन मे सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ अपने संघटक दलो से सम्बद्ध यूनियनो के सदस्य कर्मचारी एवं सम्बन्धित संस्थानो के हितो की रक्षा हेतु सरकार का आवाहन करती है कि वह निगमीकरण एवं निजीकरण की तरफ बढ़ते अपने कदमो को पीछे ले एवं इन संस्थानो को और मजबूत करने का कार्य करे।

प्रस्तावक द्वारा श्री साधू सिंह, महासचिव, जी0ई0एन0सी0
अनुमोदक द्वारा श्री अशोक शुक्ला, महासचिव, भा0रे0म0सं0